



MUFIN GREEN FINANCE LIMITED

Formerly known as APM Finvest Ltd.

To,
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400 001

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Ref: BSE Scrip Code 542774

Ref: MUFIN

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement-Unaudited Financial Results

Dear Sir/Madam,

Further to our letter dated November 14, 2024, regarding approval of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2024. please find enclosed newspaper advertisements published on November 15, 2024, in compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in "The Indian Express" (English) and "Prabhat Abhinandan" (Hindi).

This is for your information and record.

Thanking you,

For Mufin Green Finance Limited

Kapil Garg
Managing Director

Date: 15.11.2024

Place: Delhi

CIN : L65990RJ2016PLC054921



011-42610483



www.mufingreenfinance.com



connect@mufingreenfinance.com

Corporate office : 202, 2nd Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi -110034

Registered Office : SP-147, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Distt. Alwar, Rajasthan-301019

AAVAS FINANCIERS LIMITED (CIN:L65992R2011PLC034297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020. POSSESSION NOTICE

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED Registered Office: TC NO.142074/7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO - U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescendo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Email id: authorised.officer@muthoot.com

Appendix-IV(Rule 8(1)) Possession Notice (For Immovable Property) Table with columns: Sr. No., Name of Borrower / Co-Borrower / Guarantor, Date of Demand notice, Total O/S Amount (Rs.), Date of Possession

YES BANK Branch Office: 4th Floor, Anand Bhawan, Plot No. 307, Sansar Chandra Road, Chowkri Haveli, Jaipur - Raj. - 302001. Registered Office: Yes Bank House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055. Sale Notice For Sale Of Immovable Properties

MUFIN GREEN FINANCE LIMITED (CIN: L65990RJ2016PLC054921) Registered Office: SP-147, RIICO, Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan-301019. Corporate Office: 201, 2nd Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034

Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2024. Table with columns: Particulars, Quarter Ended (30.09.2024, 30.09.2023), Half Year Ended (30.09.2024, 30.09.2023), Year Ended (31.03.2024)

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2024. Table with columns: Particulars, Quarter Ended (30.09.2024, 30.09.2023), Half Year Ended (30.09.2024, 30.09.2023), Year Ended (31.03.2024)

INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI NABL/ISO 17025:2017 Certified Unit. A Unit of Security Printing and Minting Corporation of India Limited. CIN: U22213DL2006GO144763. Mini-Ratna Category - CPSE (Wholly owned by Govt. of India) Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai-400 001

BOOKING OF "250 Years of Mazagon Dock Shipbuilders Limited" and "75th Foundation Year of Central Silk Board" Commemorative Coin Sets

Table with columns: Theme, Proof (Rs.), UNC (Rs.). Rows include 250 Years of Mazagon Dock Shipbuilders Limited, 75th Foundation Year of Central Silk Board, etc.

BMB MUSIC AND MAGNETICS LIMITED Registered Office:- B-175, Devi Nagar, New Sangarner Road, Jaipur, Rajasthan - 302019. STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 2nd QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2024

KASTOOR CHAND BOKADIA CHANG DIRECTOR DIN : 01828803. SOHANKAWAR KASTOOR CHAND BOKADIA DIRECTOR DIN : 03592230. Place: Jaipur Date: 14.11.2024

Mahindra FINANCE Registered Office at: Gateway Building, Apollo Bunder, Mumbai-400 001. Corporate office at: B Wing, 3rd Floor, Agastya Corporate Park, Piramal Amli Building, Kamani Junction, Kuria West Mumbai-400 070. NOTICE TO BORROWER UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.

Malviya Nagar Branch, C-30, Hari Marg, Opp. Kardiham Shopping Centre, Malviya Nagar, Jaipur-302017, Rajasthan. POSSESSION NOTICE (For movable property) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD. AUCTION NOTICE This is to inform the public at large, that FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD., has decided to conduct Auction of Gold ornaments belonging to accounts (mentioned below) which have become overdue or which have defaults or margin breach customers.

Ac Engitech Limited (Formerly known as Prem Sonani Financial Services Limited) Extract of Financial Results for the Quarter ended 30th September 2024. Table with columns: S. No., Particulars, Quarter ended 30/09/2024, Quarter ended 30/09/2023

Registered Office : 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in. LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://goc.samil.in) BAGRU - L9001090139193742 L9001090141398170 L9001090440757032 | BALEGAR - L9001090137651042 L9001090139136002 | BALOTRA - L9001090136016942 | BANWARA - 24660000955530 | BARMER - L9001090137999221 | BILHWARA - 2366000146743 23660002165443

अपनाघर शालीमा सोसायटी के गार्ड की मौत

अलवर/बहरोड़, 14 नवम्बर (वेबवार्ता)। सदर थाना क्षेत्र में छठी मील के पास हुए रोड एक्सीडेंट के सात दिन बाद अपनाघर शालीमा के सुरक्षा गार्ड बहादुरपुर निवासी 26 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई चिराग सेन ने बताया कि उसका छोटा भाई विष्णु सेन अपनाघर शालीमा आवासीय सोसायटी में वतौर सुरक्षा गार्ड काम करता है। वह बहादुरपुर से रोजाना बाइक से ड्यूटी आता था। 7 नवंबर को ड्यूटी पर आते समय छठी मील के समीप देर शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गंभीर घायल हुए थे। जिसे इलाज के दौरान जयपुर रेफर कर दिया गया था। वहां से छुट्टी मिलने के बाद घर आ गए थे। लेकिन घर आने के बाद वापस तबीयत बिगड़ गई। जिसे जिला अस्पताल अलवर लाया गया। लेकिन यहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के बाद शव सुपुर्द कर दिया।

पूर्व MLA बोले- रामगढ़ में बूथ कैप्चरिंग रुकी

अलवर/बहरोड़, 14 नवम्बर (वेबवार्ता)। पूर्व विधायक रामेंद्र गंडूरा रामगढ़ चुनाव के दो दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। मतदान के अगले दिन वे बोले- रामगढ़ में बीजेपी चुनाव जीतेगी। यहां इस बार बूथ कैप्चरिंग रुकी है, जिससे कांग्रेस का वोट ज्यादा प्रभावित हुआ है। इससे पहले कांग्रेस ही बूथ कैप्चरिंग करती रही है। प्रदेश भर में बीजेपी सबसे ज्यादा सीट जीतेगी। उप चुनाव में संभव है कि सातों सीट जीत जाएं। रामेंद्र गंडूरा ने खुद के कांग्रेस छोड़ने का कारण बताते हुए कहा- वह लंबे समय से कांग्रेस में है लेकिन वहां उपेक्षा होती रही। 20 साल में कोई पद तक नहीं दिया। इस कारण चुनाव के समय कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। फर्जी वोटिंग कम हुई गंडूरा ने कहा- बीजेपी प्रत्यासी की जीत होगी। जिसका मुख्य



कारण सरकार के कार्य और मतदाताओं का जोश है। सरकार के 11 महीने के काम से जनता प्रभावित है। यह सही है कि इस बार रामगढ़ में पहले वोटिंग कम हुई है लेकिन जहां

25 साल की महिला की मौत

अलवर/बहरोड़, 14 नवम्बर (वेबवार्ता)। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ओडपुर गांव में 25 वर्षीय विवाहिता की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। सीने में दर्द होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। राजगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि ओडपुर गांव निवासी 25 वर्षीय पूनम मीणा की शादी 2009 में हुई थी। जो पिछले करीब एक वर्ष से बीमार चल रही थी। बुधवार देर शाम अचानक से सीने में दर्द हो गया। उसके बाद जिला अस्पताल राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। लेकिन देर रात करीब 2 बजे के समीप महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के लोगों का मानना है कि अचानक हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। महिला के पति बाबूलाल मीणा खेती बाड़ी करते हैं।

49 नगर निकायों में प्रशासक लगाने की तैयारी

जयपुर, 14 नवम्बर (वेब वार्ता)। राजस्थान के 49 नगर निकायों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है। लेकिन अब तक निकायों के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। जिसको लेकर अब जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही प्रदेश के 49 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल का प्रावधान है। इसी तरह राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 7 में भी नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल से



ज्यादा नहीं होने का प्रावधान है। ऐसे में कि अगर नगरपालिका में यदि कार्यकाल के 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले चुनाव नहीं कराए जाते हैं। तो बोर्ड खुद-ब-खुद भंग हो जाता है। ऐसे में वहां सरकार चुनाव होने तक प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एक प्रदेश एक चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश की 49 नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर सकती है। चुनाव आयोग करेगा फैसला प्रदेशभर में जारी इस असमंजस की स्थिति को लेकर यूडीएच मंत्री ज्ञान सिंह खर्रां ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लेने का हवाला दिया है। खर्रां ने कहा कि चुनाव घोषित करने का काम राज्य

निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में कोई कदम बढ़ाएगा। तो हम उसके मुताबिक कोई फैसला लेंगे। वहीं अगर राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया। तो कार्यकाल बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। इन दोनों ही फसलों को लेकर अगले सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। प्रशासक की करनी होगी नियुक्ति डीएलबी के पूर्व डायरेक्टर लॉ अशोक सिंह ने कहा कि नियमों के तहत नगर निकायों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में अगर 5 साल की समय अवधि के दौरान नगर निकायों के चुनाव संभव नहीं हुए। तो सरकार को सभी नगर निकायों में जहां का भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा आईसीएमआर: अनुग्रिया पटेल

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुग्रिया पटेल ने देश में वैज्ञानिक नवाचार बढ़ाने में आरंभिक परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा अलग-अलग दो दिन में आयोजित करने के फैसले के खिलाफ चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, "जो लोग 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की बात करते हैं, वे एक दिन में छात्रों के लिए परीक्षा भी नहीं करवा सकते।"

जो लोग 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की बात करते हैं, वे एक दिन में परीक्षा तक नहीं करा सकते: अखिलेश



प्रयागराज (उप्र), 14 नवंबर (वेब वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने और परीक्षाओं को ठीक से आयोजित करने में विफल रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की आलोचना की। फूलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने उग्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा

यादव ने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की, लेकिन राजनीतिकरण के आरोपों से बचने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से परहेज किया। उन्होंने राज्य में परीक्षाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में असमर्थता के लिए भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा, "यह वही सरकार है जो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को बढ़ावा देती है, लेकिन उग्र प्रदेश में वे हमारे युवाओं के लिए एक दिन में परीक्षा तक नहीं करा सकते। प्रयागराज में हजारों छात्र इस फैसले के खिलाफ लगातार चौथे दिन बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन किया बिनका टाबा है कि इससे अनावश्यक भ्रम और कठिनाई बढ़ रही है। यादव ने प्रश्नपत्र लौक, बार-बार परीक्षा के स्थगित और रह होने जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है।

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया कि अगर व्हाट्सएप देश में अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके संचालन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वह केरल निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमनाकुट्टन केजी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। ओमनाकुट्टन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि 'मैसेजिंग प्लेटफॉर्म' ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करने से इनकार कर दिया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

एनआईए ने कश्मीर में दो गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल आरोपी की अवल संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण (एनआईए) ने इस साल कश्मीर में दो गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल एक प्रमुख आरोपी की अवल संपत्ति जब्त की है। बृहस्पतिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि आरोपी आदिल मंजूर लंगू आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) की शाखा 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ)' से जुड़ा है। यह जब्त लंगू तथा दो अन्य लोगों अहरान रसूल डार और दाऊद द्वारा रची गई साजिश से संबंधित मामले की जांच के सिलसिले में की गई। बयान में कहा गया है, 'पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के आकाओं के नेतृत्व में इस साजिश का उद्देश्य भारत में निर्दोष लोगों की हत्या करना और आतंक फैलाना तथा हिंसा भड़काना था।' इसमें कहा गया है कि सात फरवरी को दो गैर स्थानीय लोगों की हत्या के बाद जांच में लंगू, डार और दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मास्टरमाइंड जहांगीर अभी भी फरार है। बयान में कहा गया कि अपराध में इस्तेमाल किये गये हथियार और कारतूस बरामद कर लिये गये हैं। यह बरामदगी लंगू की 10 मरला अवल संपत्ति से की गई। इसमें कहा गया है कि श्रीनगर के जाल्दगार में स्थित संपत्ति को बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 25 के तहत जब्त कर लिया गया। जांच एजेंसी ने बताया कि लंगू को 12 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये गये थे। लंगू फिलहाल श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद है।

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। आबरवैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शामिल वार्ताकारों को दुनिया में बढ़ते तापमान से निपटने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में विकासशील देशों की मदद के लिए 2030 तक प्रति वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बृहस्पतिवार को 'इंडिपेंडेंट हार्ड-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज' का 'फाइनेंस' (आईएचएलईजी) की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त विशेषज्ञों के समूह के अनुसार, इस धन की आवश्यकता सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से है। यह रिपोर्ट जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड समेत कई अमीर देशों द्वारा यह स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद आई है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खरबों डॉलर की तत्काल आवश्यकता है और अमीर देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने में आगे रहना चाहिए। सम्मेलन में शामिल देश 2025 के बाद विकासशील देशों की मदद के लिए एक नए जलवायु वित्त पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2030 से पहले निवेश में किसी भी तरह की कमी होने से आने वाले वर्षों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जिससे जलवायु स्थिरता के लिए राह कठिन हो जाएगी और वित्तीय बोझ भी बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अब पर्याप्त निवेश नहीं किए जाने का मतलब है कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कम समय सीमा में और भी बड़ी रकम जुटाने की आवश्यकता होगी। जलवायु कार्यकर्ता और जीवाणु ईंधन अप्रसार संधि पहल के वैश्विक कार्यक्रम निदेशक हरजीत सिंह ने कहा, 'बार-बार यह चेतावनी दी गई है कि

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। आबरवैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शामिल वार्ताकारों को दुनिया में बढ़ते तापमान से निपटने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में विकासशील देशों की मदद के लिए 2030 तक प्रति वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बृहस्पतिवार को 'इंडिपेंडेंट हार्ड-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज' का 'फाइनेंस' (आईएचएलईजी) की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त विशेषज्ञों के समूह के अनुसार, इस धन की आवश्यकता सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से है। यह रिपोर्ट जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड समेत कई अमीर देशों द्वारा यह स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद आई है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खरबों डॉलर की तत्काल आवश्यकता है और अमीर देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने में आगे रहना चाहिए। सम्मेलन में शामिल देश 2025 के बाद विकासशील देशों की मदद के लिए एक नए जलवायु वित्त पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2030 से पहले निवेश में किसी भी तरह की कमी होने से आने वाले वर्षों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जिससे जलवायु स्थिरता के लिए राह कठिन हो जाएगी और वित्तीय बोझ भी बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अब पर्याप्त निवेश नहीं किए जाने का मतलब है कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कम समय सीमा में और भी बड़ी रकम जुटाने की आवश्यकता होगी। जलवायु कार्यकर्ता और जीवाणु ईंधन अप्रसार संधि पहल के वैश्विक कार्यक्रम निदेशक हरजीत सिंह ने कहा, 'बार-बार यह चेतावनी दी गई है कि

कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहां जब तक नए बोर्ड का गठन नहीं होगा। तब तक वहां प्रशासक की नियुक्ति करनी होगी। इन निकायों में पूरा हो रहा कार्यकाल राजस्थान की बीकानेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, व्यावर, नसीरगढ़, टोंक, डीडवाना, पुष्कर, चूरू, मकरान, अलवर, भिवाड़ी, धानागाजी, महुआ, सीकर, नीमकाधाना, खाटूयाजमी, बाड़मेर नगरपरिषद, बलौता, सिरौही, माउंटआबू, पिण्डवाड, लिपार्गज, पाली, झुंझुनू, बिसास, पिलानी, फलीदी, जैसलमेर, सुमेरपुर, उदयपुर, सनोद, वांसवाडा, प्रतापगढ़, गढ़ी, चित्तौड़गढ़, निम्बहेड़, रवतभाट, वजसमंद, आमेट, भरतपुर, रूपवास, जालौर, भीनमाल, कैथून, सांगोद, छबड़, मंगरोल का कार्यकाल पूरा होने को है।

विकासशील देशों को 2030 तक प्रति वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 14 नवंबर (वेब वार्ता)। आबरवैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में शामिल वार्ताकारों को दुनिया में बढ़ते तापमान से निपटने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में विकासशील देशों की मदद के लिए 2030 तक प्रति वर्ष एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बृहस्पतिवार को 'इंडिपेंडेंट हार्ड-लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज' का 'फाइनेंस' (आईएचएलईजी) की नई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त विशेषज्ञों के समूह के अनुसार, इस धन की आवश्यकता सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से है। यह रिपोर्ट जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड समेत कई अमीर देशों द्वारा यह स्वीकार किए जाने के एक दिन बाद आई है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए खरबों डॉलर की तत्काल आवश्यकता है और अमीर देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने में आगे रहना चाहिए। सम्मेलन में शामिल देश 2025 के बाद विकासशील देशों की मदद के लिए एक नए जलवायु वित्त पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2030 से पहले निवेश में किसी भी तरह की कमी होने से आने वाले वर्षों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जिससे जलवायु स्थिरता के लिए राह कठिन हो जाएगी और वित्तीय बोझ भी बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अब पर्याप्त निवेश नहीं किए जाने का मतलब है कि महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कम समय सीमा में और भी बड़ी रकम जुटाने की आवश्यकता होगी। जलवायु कार्यकर्ता और जीवाणु ईंधन अप्रसार संधि पहल के वैश्विक कार्यक्रम निदेशक हरजीत सिंह ने कहा, 'बार-बार यह चेतावनी दी गई है कि

कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को लूटा



नई दिल्ली, 14 नवम्बर (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पनवेल में विशाल जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है, बीजेपी और

वहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें स्वराज की शपथ दिलाई थी। हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वराज के साथ-साथ सुराज के संकल्प को आगे बढ़ाना है। स्वराज का ये संकल्प तब पूरा होगा जब हमारा गरीब आगे बढ़ेगा। इस संकल्प की सिद्धि का काम केवल भाजपा और महायुति सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महायुति इसी संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। अपने संबोधन की शुरुआत में मोदी ने कहा कि मेरा सीमाध्य है कि आज मुझे एक बार फिर रायगढ़ को इस मिट्टी को फिर से नमन करने का अवसर मिला है। रायगढ़ से मेरा एक आत्मीय और भावात्मक संबंध है। उन्होंने कहा कि 2013 में जब भाजपा ने मुझे पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तब मैंने रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था। मोदी ने कहा कि 23 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं, उसकी गारंटी

गरीबी से बाहर लाई है। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार की नीतियां आज शोषितों और वंचितों की ताकत बन रही है। जो काम 10 साल में हुए, वो काम पहले भी हो सकते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि गरीब आगे आकर अपना हक मांगे। इसलिए आज भी कांग्रेस गरीबों के लिए कल्याण की हर योजना का जमक विरोध करती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि जो 25 करोड़ लोग गरीबों से बाहर निकले हैं, उन्हें मुफ्त राशन क्यों मिल रहा है। कांग्रेस चाहती है कि इन लोगों का खर्च बढ़े और वे फिर से गरीबों में चले जाएं। अगर अभाड़ी वालों को मौका मिला तो वे महाराष्ट्र में वही करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां वे गरीबों को मुफ्त राशन देने पर हमसे सवाल कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के एक मंत्री ने हिंदुओं, मुसलमानों और पुरुषपतिव्यों को भी मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की है। वे खुलेआम रोहिंग्य और बांग्लादेशियों को मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि वोट पाने के लिए वे किस तरह देश और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल खेल रहे हैं।

मणिपुर में हिंसा पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

मणिपुर, 14 नवम्बर (वेब वार्ता)। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में गुरुवार को कहा गया कि मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को समीक्षा के बाद पहले से बाहर किए गए 19 पुलिस स्टेशनों में से छह को एफएफपीए के तहत कवर किया जा रहा है। एमएचए के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि यह देखा गया है कि मणिपुर में चल रही जातीय हिंसा के बीच स्थिति अस्थिर बनी हुई है और बिष्णुपुर-चुराचांदपुर, इम्फाल पूर्व, कांगपोकपी-इम्फाल पश्चिम और

चिरीबाम जिलों के सीमांत इलाकों में हिंसाप्रस्त क्षेत्रों में रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है, जिसमें विद्रोहियों को सक्रिय भागीदारी के कई उदाहरण हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर में छह पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया, इन क्षेत्रों को भी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम या एफएफपीए, 1958 के तहत लाया गया। पहले 19 पुलिस स्टेशनों को अफस्य से बाहर रखा गया था। यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकों पर ताजा हमलों

और बलों और उग्रवादियों के बीच नए सिरे से हुई गोलीबारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ मणिपुर में 20 अतिरिक्त अर्धसैनिक कर्पणियों या लगभग 2,500 कर्मियों को भेजने के एक दिन बाद आया है, जो उस राज्य में बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है जहां 230 से अधिक लोग मारे गए हैं। लगभग 18 महीने पहले शुरू हुई झड़पों में उनकी मौत हो गई। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में गुरुवार को कहा गया कि मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद पहले से बाहर किए गए।

विश्वीय सहायता प्रदान करने में देरी करते रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए 2030 तक सालाना 6.3 - 6.7 लाख

निष्क्रियता से खर्च बढ़ेगा और जलवायु स्थिरता का मार्ग कठिन होगा, इसके बावजूद अमीर देश अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए विकासशील देशों को

वित्तीय सहायता प्रदान करने में देरी करते रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए 2030 तक सालाना 6.3 - 6.7 लाख

करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है जबकि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए 2.4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की जरूरत है।

मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड							
सीआईएन: L65990RJ2016PLC054921							
पंजीकृत कार्यालय: एसपी-147, शिको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान-301019							
कारपोरेट कार्यालय: 201, दूसरी मंजिल, बेट्ट स्कॉई टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतम्पुरा, दिल्ली-110034							
ई-मेल: apnfinvestltd@gmail.com वेबसाइट: www.mufingreenfinance.com दूरभाष: 011-43094300							
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष							
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		छमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)		31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालन से कुल आय	4,044.92	3,738.41	2,101.21	7,783.33	3,855.22	9,843.74
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं और खर्च से पहले)	805.71	623.79	536.95	1,429.50	1,000.45	2,175.69
3.	कर से पहले वर्ष / अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के बाद)	805.71	623.79	536.95	1,429.50	1,000.45	2,123.40
4.	कर और असाधारण मदों के बाद वर्ष / अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	571.07	462.08	400.86	1,033.15	745.57	1,606.39
5.	वर्ष / अवधि के लिए कुल व्यापक आय [वर्ष / अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	574.73	462.59	403.74	1,037.32	745.59	1,608.42
6.	इन्विस्टी शेयर पूंजी	1,628.70	1,628.70	1,509.95	1,628.70	1,509.95	1,621.05
7.	अन्य इन्विस्टी	-	-	-	-	-	22,788.90
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 1 रुपये)	0.35	0.28	0.26	0.63	0.49	1.05
1.	मूल	0.34	0.28	0.26	0.62	0.49	1.05
2.	तरल	-	-	-	-	-	-
	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष							
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		छमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)		31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालन से कुल आय	4,634.52	3,734.55	2,101.21	8,369.07	3,855.22	9,843.74
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं और खर्च से पहले)	800.67	591.84	536.75	1,392.51	1,000.25	2,175.49
3.	कर से पहले वर्ष / अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण वस्तुओं के बाद)	800.67	591.84	536.75	1,392.51	1,000.25	2,123.20
4.	कर और असाधारण मदों के बाद वर्ष / अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि)	567.30	438.17	400.66	1,005.47	745.37	1,606.19
5.	वर्ष / अवधि के लिए कुल व्यापक आय [वर्ष / अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं]	570.96	438.68	403.54	1,009.64	745.39	1,608.22
6.	इन्विस्टी शेयर पूंजी	1,628.70	1,628.70	1,509.95	1,628.70	1,509.95	1,621.05
7.	अन्य इन्विस्टी	-	-	-	-	-	22,788.70
8.	प्रति शेयर आय (प्रत्येक 1 रुपये)	0.35	0.27	0.26	0.62	0.49	1.05
1.	मूल	0.34	0.27	0.26	0.61	0.49	1.05
2.	तरल	-	-	-	-	-	-
	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया	वार्षिक नहीं किया गया
30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष							
नोट:							
1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 14 नवंबर, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किया गया है। कंपनी के वित्तीय लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की है।							
2. उपरोक्त 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राकृत्य का एक अंश है, जिसे संशोधित रूप में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया है।							
30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्राकृत्य कंपनी की वेबसाइट www.mufingreenfinance.com के निवेशक अनुभाग के अंतर्गत और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है।							
मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के लिए							
हस्ता/कपिल गर्ग							
प्रबंध निदेशक							
तिथि: 14.11.2024							
स्थान: नई दिल्ली							